

## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 008/2018 (GCMS 2018/00195)	दायर दिनांक 19.01.2018	निर्णय दिनांक 24.02.2021
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी****बनाम**

श्यामलाल पुत्र बंशीलाल सेठिया (विक्रेता/मालिक)  
मैसर्स सेठिया मिष्ठान भण्डार, चित्तौड़-कपासन रोड़ ग्राम सिंहपुर  
तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़,  
निवासी ग्राम सिंहपुर, तहसील जिला चित्तौड़गढ़ राज.

**अप्रार्थी**

**-:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट  
2006 नियम 2011 :-**

**-:: निर्णय :-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपेन्द्र मिश्रा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/ 465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था एवं उपेन्द्र मिश्रा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक FSSA/F-168/2015/491 दिनांक 29.06.2015 के अनुसार उन्हे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य



सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2015 को समय 01.35 पी.एम. पर ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर पहुंचे। वहां पर श्यामलाल पुत्र बंशीलाल सेठिया (विक्रेता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं उमेश कुमार सेठिया की उपस्थिति में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर कॉच के काउन्टर में एक एल्यूमिनीयम ट्रे में लगभग 5 किलो मावा बर्फी तैयार की रखी पाई गई। व्यापारी ने बताया कि उक्त मावा बर्फी आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु तैयार की गई है एवं विक्रय की जा रही है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर V A की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावा बर्फी जो कि लगभग 5 किलो थीं में से 2 किलोग्राम मावा बर्फी वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपये 500/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा मावा बर्फी को चार बराबर भागों में बाँट कर चार प्लास्टिक जारों में अलग-अलग भरकर फोर्मलिन की 40-40 बुन्दे डालकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-587 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाईं और एवं एक बाईं और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पुर्ण विवरण लिखकर उनके द्वारा हस्ताक्षर



कर चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सीलड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 को अलग से सीलड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/3973 दिनांक 17.11.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावा बर्फी का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब्सटेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स सेठिया मिष्ठान भण्डार, चित्तौड़-कपासन रोड़ ग्राम सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को प्राप्त जाँच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई थी। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 3973 दिनांक 17.11.2015 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/642 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/स.सी./2017/1006 दिनांक 03.10.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। साथ ही अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/4438 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा आवेदक



खाद्य सुरक्षा अधिकारी न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, का पत्र मुल संलग्न है। उक्त प्रकरण में निम्न अभियुक्त ने सस्सटेण्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अंत में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन श्रीमान को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 16.03.2018 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता बीएल पोखरना हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 26.04.2018 को अप्रार्थी की और से जवाब परिवाद पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर बताया कि अभियुक्त श्याम लाल सेठिया से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधि अनुसार सेम्पल नहीं लिया गया और सेम्पल लेने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया जिस कारण अभियुक्त/विपक्षी श्याम लाल के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्तनीय है। तथाकथित मावा बर्फी के सेम्पल की विधि अनुसार अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा जांच नहीं की गयी। फुड एनालिस्ट फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री उदयपुर विधि अनुसार जांच हेतु अधिकृत प्रयोगशाला नहीं है और जो जांच की प्रक्रिया अपनायी गयी वह भी विधि अनुसार अधिकृत प्रक्रिया नहीं है। घी के निर्धारित मानक आईटम 2.1.10.3 को आधार मानकर जो मावा बर्फी की जांच रिपोर्ट दी गयी वो गलत है, क्योंकि मावा बर्फी रेगुलेशन नंबर 2.1.1 फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन 2011 होनी चाहिए जो जांच रिपोर्ट से नहीं है, इस कारण सारी कार्यवाही दूषित व खारिज होने योग्य है। फुड एनालिस्ट पंकज कुमार को भी विधि अनुसार जांच करने हेतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है इस कारण उसके द्वारा की गयी जांच विधि अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त/विपक्षी श्याम लाल फुड एनालिस्ट पंकज कुमार को जिरह हेतु साक्ष्य में न्यायहित में बुलवाना चाहता अतः उसे न्यायहित में न्यायालय में उपस्थित रखने हेतु परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पाबंद किया जाए। धारा 46 (4) के अनुसार वांछित सूचना एवं जांच रिपोर्ट अभियुक्त को न तो सही पते पर भेजी गयी और न अभियुक्त/विपक्षी को प्राप्त हुई इस कारण वह नमूने की दुबारा जांच कराने के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार से वंचित हुआ है इस कारण समूची कार्यवाही अभियुक्त/विपक्षी के विरुद्ध खारिज किये जाने योग्य है,



उपरोक्त आपत्तियों के साथ विकल्प में अभियुक्त/विपक्षी का निवेदन है कि अभियुक्त/विपक्षी श्याम लाल वृद्ध व्यक्ति है वह सिंहपुर के छोटे से गांव में अपने पुत्र सत्यनारायण की दुकान पर मात्र इस कारण सेम्पलिंग के समय बैठा था कि सत्यनारायण घर पर खाना खाने गया हुआ था, जहां से सेम्पल लिया गया वह बहुत छोटी सी गांव की दुकान है और मात्र थोड़ी ही मावा बर्फी थी अभियुक्त/विपक्षी बड़ा व्यापारी नहीं है और छोटा सा मामला है ऐसी स्थिति में धारा 49 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों अंतर्गत यह मामला ऐसा है कि जिसमें माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी श्रीमान एक गांव के छोटे व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद को मामूली जुर्माना से दण्डित करें, इसी में न्याय का हित है क्योंकि यह प्रथम अपराध है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त/विपक्षी श्याम लाल के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद प्रथमतः निरस्त फरमाया जाए, विकल्प में उपर जवाब में वर्णित तथ्यानुसार धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त/विपक्षी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए मामूली जुर्माना पर मामले को निर्णित फरमाया जावे। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 24.02.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर आयें एवं बहस पत्रावली की गई। अपनी बहस पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधि अनुसार सेम्पल नहीं लिया गया और सेम्पल लेने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया जिस कारण विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्तनीय है। फुड एनालिस्ट फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री उदयपुर विधि अनुसार जांच हेतु अधिकृत प्रयोगशाला नहीं है, और जो जांच की प्रक्रिया अपनायी गयी वह भी विधि अनुसार अधिकृत प्रक्रिया नहीं है। घी के निर्धारित मानक आईटम 2.1.10.3 को आधार मानकर जो मावा बर्फी की जांच रिपोर्ट दी गयी वो गलत है, क्योंकि मावा बर्फी रेगुलेशन नंबर 2.1.1 फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन 2011 होनी चाहिए जो जांच रिपोर्ट से नहीं है, इस कारण सारी कार्यवाही दूषित व खारिज होने योग्य है। फुड एनालिस्ट पंकज कुमार को भी विधि अनुसार जांच करने हेतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है इस कारण उसके द्वारा की गयी जांच विधि अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी फुड एनालिस्ट को जिरह हेतु साक्ष्य में न्यायहित में बुलवाना चाहता अतः उसे न्यायहित में न्यायालय में उपस्थित रखने हेतु परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पाबंद किया जाए। धारा 46 (4) के अनुसार वांछित सूचना एवं जांच रिपोर्ट अभियुक्त को न तो सही पते पर भेजी गयी और न विपक्षी को प्राप्त हुई इस कारण वह नमूने की दुबारा जांच कराने के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार से वंचित हुआ है इस कारण समूची कार्यवाही विपक्षी के विरुद्ध खारिज किये जाने योग्य है। इसके साथ ही विपक्षी वृद्ध व्यक्ति है वह सिंहपुर के छोटे से गांव में अपने पुत्र की दुकान पर मात्र



इस कारण सेम्पलिंग के समय बैठा था कि उसका पुत्र घर पर खाना खाने गया हुआ था, जहां से सेम्पल लिया गया वह बहुत छोटी सी गांव की दुकान है और मात्र थोड़ी ही मावा बर्फी थी विपक्षी बड़ा व्यापारी नहीं है और छोटा सा मामला है ऐसी स्थिति में धारा 49 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों अंतर्गत यह मामला ऐसा है कि जिसमें माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी श्रीमान एक गांव के छोटे व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद को मामूली जुर्माना से दण्डित करें, इसी में न्याय का हित है क्योंकि यह प्रथम अपराध है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपान्त अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। सुनी गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को मावा बर्फी का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.10.2015 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.10.2015 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा बर्फी जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-587 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 68 से सील चपड़ी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2015/4 दिनांक 22.10.2015 से पत्रवाहक महेन्द्र सिंह (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-587 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्र सिंह (सहायक कर्मचारी) द्वारा उक्त



नमूना मय लिफाफे के दिनांक 23.10.2015 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2015/3973 दिनांक 17.11.2015 से विपक्षी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 555/Act/2015/573 Dated 29-10-2015 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 555/Act/2015/573 Dated 29-10-2015 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

**Report No. LS 555/Act/2015/573 Dated 29-10-2015**

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Upendra Mishra Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Mawa burfi bearing code no. and serial no. AM- 587 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 23.10.2015 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 68 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Mawa burfi falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 29.10.2015 and the result of its analysis is given below-

**ANALYSIS REPORT---**

- (i) Sample description:- The Sample contained in a wide mouth plastic jar screwed with lid.
- (ii) Physical appearance:- Creamish in color.
- (iii) Label :- Loose Sample of Mawa burfi.

Opinion:- The sample Mawa burfi Bearing code no. and serial no. AM- 587 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as Butyrefractometer reading at 40° C does not meet the specified standards as prescribed in Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील से सील अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 23.10.2015 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि Mawa burfi falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-587 मावा बर्फी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब्सटेण्डर्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य



विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। इसके साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब परिवाद में खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की वैद्यता का प्रश्न उठाया गया। इस संबंध में खाद्य विश्लेषक, उदयपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि खाद्य विश्लेषक पंकज कुमार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत राजस्थान राज्य में नियुक्त किया गया जो कि विधि अनुसार है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी उक्त मावा बर्फी का नमूना लिये जाने में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट को अन्तर्गत धारा 46(4) के संबंध में विपक्षी को प्रेषित किये जाने का प्रश्न है तो अभिहित अधिकारी द्वारा विपक्षी द्वारा दिये गये पते पर ही जरिये पत्र से प्रेषित किया जाना जाहिर होता है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2015/3973 दिनांक 17.11.2015 का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा विपक्षीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया, इस संबंध में विपक्षी द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना ही जाहिर होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2017/642 दिनांक 16.02.2017 से आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान को समय सीमा विस्तार हेतु निवेदन किया गया। इस पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के तहत अपने आदेश क्रमांक/एफएसएसए/स.सी./2017/997 दिनांक 03.10.2017 से समय सीमा का विस्तार किया गया। जिसके लिये आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 में वर्णित प्रावधानों के तहत सक्षम है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2017/4438 दिनांक 26.10.2017 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इसके साथ आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के संबंध में समस्त तथ्य पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं



मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, इसके साथ ही विक्रेता का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :-

**25. All imports of articles of food to be subject to this Act.**

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

**26. Responsibilities of the Food business operator.**

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence



that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

**27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers**

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is—
  - (a) Supplied after the date of its expiry; or
  - (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
  - (c) Unsafe or misbranded; or
  - (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
  - (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
  - (f) received by him with knowledge of being unsafe.
- (2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is —
  - (a) sold after the date of its expiry; or
  - (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
  - (c) misbranded; or
  - (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
  - (e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे विपक्षी श्री श्यामलाल पुत्र बंशीलाल सेठिया (विक्रेता/मालिक) मैसर्स सेठिया मिष्ठान भण्डार, चित्तौड़-कपासन रोड़ ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़, निवासी ग्राम सिंहपुर, तहसील जिला चित्तौड़गढ़ राज. को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष



सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार-

**49. General provisions relating to penalty.**

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

- (a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
- (b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
- (c) The repetitive nature of the contravention,
- (d) Whether the contravention is without his knowledge, and
- (e) Any other relevant factor,

**51. Penalty for sub-standard food.**

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त श्री श्यामलाल पुत्र बंशीलाल सेठिया (विक्रेता/मालिक) मैसर्स सेठिया मिष्ठान भण्डार, चित्तौड़-कपासन रोड़ ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़, निवासी ग्राम सिंहपुर, तहसील जिला चित्तौड़गढ़ राज. को रूपये 7,500/- अक्षरे सात हजार पांच सौ रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि नियत समयावधि में अभियुक्तगण से शास्ति राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करावें एवं नियत समयावधि में अभियुक्तगण द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
जिला चित्तौड़गढ़